



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 2006/पौष 9, 1928

No. 613]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 2006/PAUSA 9, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2006

संख्या 30/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 780(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 को आगे संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात्;

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2006 कहा जायेगा।  
(2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में, नियम 12 ग. के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जायेगा, जिसका नाम है :-

“12 ग.ग. कतिपय प्रकार के मामलों में प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ केन्द्र सरकार, शुल्क अपवचन, अपराधों की प्रकृति और प्रकार, अथवा ऐसे अन्य कारण, जो कि संगत हो, के सम्बन्ध में, की राय है, कि उत्पाद शुल्क की वचना तथा इसके भुगतान में चूक को रोकने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी विनिर्माता, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के डीलर अथवा किसी निर्यातक पर प्रतिबन्धों सहित कुछ उपायों का प्रावधान करना जनहित में आवश्यक है, डीलर के मामले में पंजीकरण के निलम्बन, वापस ली जाने वाली सुविधाओं के प्रकार सहित प्रतिबन्धों की प्रकृति बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश को जारी करने की प्रक्रिया तथा अपील प्रक्रिया को, विनिर्दिष्ट कर सकती है।”

[फा. सं. 224/40/2006-के.उ.शु.-6]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम दिनांक 01 मार्च, 2002 अधिसूचना संख्या 04/2002-के. उ. शु. (गै.टै.), [सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक . 01 मार्च, 2002] के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये गये थे, तथा [सा.का.नि. 771(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2006] द्वारा अधिसूचना संख्या 26/2006-के. उ. शु. (गै.टै.) दिनांक 28 दिसम्बर, 2006, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2006

**No. 30/2006-Central Excise (N.T.)**

**G.S.R. 780(E).**— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 2006.  
  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 2002, after rule 12C, the following rule, shall be inserted, namely :-

“12CC. Power to impose restrictions in certain types of cases.- Notwithstanding anything contained in these rules, where the Central Government, having regard to the extent of evasion of duty, nature and type of offences or such other factors as may be relevant, is of the opinion that in order to prevent evasion of, and default in payment of, excise duty, it is necessary in the public interest to provide for certain measures including restrictions on a manufacturer, first stage and second stage dealer or an exporter, may by a notification in the Official Gazette, specify nature of restrictions including suspension of registration in case of a dealer, types of facilities to be withdrawn and procedure for issue of such order by an officer authorized by the Board”.

[F. No. 224/40/2006-CX-6]

RAHUL NANGARE, Under Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number 04/2002-CE(NT), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 [G.S.R. 143(E), dated the 1<sup>st</sup> March 2002], and were last amended vide notification number 26/2006-CE (NT), dated 28<sup>th</sup> December, 2006 vide [G.S.R. 771 (E), dated the 28<sup>th</sup> December, 2006].

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2006

संख्या 31/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टै. )

सा.का.नि. 781(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को सेनवैट क्रेडिट (सातवाँ संशोधन) नियम, 2006 कहा जाये।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में, नियम 12क के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जायेगा, जिसका नाम है :-

“12 क.क. कतिपय प्रकारों के मामलों में प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति,- इन नियमों में किसी बात के निहित होते हुए भी, जहाँ केन्द्र सरकार सेनवैट क्रेडिट के दुरुपयोग, की सीमा, ऐसे दुरुपयोग की प्रकृति एवम प्रकार तथा ऐसे अन्य कारण की सीमा तक, जैसा भी संगत हो, के सम्बन्ध में, की राय है, कि इन नियमों में यथा निर्दिष्ट सेनवैट क्रेडिट के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विनिर्माता, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के डीलर अथवा किसी निर्यातक पर प्रतिबन्धों सहित कुछ उपायों का प्रावधान करना जनहित में आवश्यक है; डीलर के मामले में पंजीकरण के निलम्बन, वापस ली जाने वाली सुविधाओं के प्रकार सहित प्रतिबन्धों की प्रकृति बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश को जारी करने की प्रक्रिया तथा अपील प्रक्रिया को, विनिर्दिष्ट कर सकती है।”

[फा. सं. 224/40/2006-के.उ.शु.-6]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान नियम अधिसूचना संख्या 23/2004- के. उ. शु. (एन. टी.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004, जी. एस. आर. 600 (ई), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किये गये तथा [जी. एस. आर. 608 (ई), दिनांक 30 सितम्बर, 2006] द्वारा अधिसूचना संख्या 19/2006- के. उ. शु. (एन. टी.), दिनांक 30 सितम्बर, 2006 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2006

No. 31/2006-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 781(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Seventh Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, after rule 12A, the following rule, shall be inserted, namely:-

“12AA. Power to impose restrictions in certain types of cases.- Notwithstanding anything contained in these rules, where the Central Government, having regard to the extent of misuse of CENVAT credit, nature and type of such misuse and such other factors as may be relevant, is of the opinion that in order to prevent the misuse of the provisions of CENVAT credit as specified in these rules, it is necessary in the public interest to provide for certain measures including restrictions on a manufacturer, first stage and second stage dealer or an exporter, may by a notification in the Official Gazette, specify nature of restrictions including restrictions on utilization of CENVAT credit and suspension of registration in case of a dealer and type of facilities to be withdrawn and procedure for issue of such order by an officer authorized by the Board”.

[F. No. 224/40/2006-CX-6]

RAHUL NANGARE, Under Secy.

Note.- The principal rules were published vide notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, G.S.R.600 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 and was last amended vide notification No.19/2006-Central Excise (N.T.), dated the 30<sup>th</sup> September, 2006, vide [G.S.R. 608(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2006].

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2006

संख्या 32/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 782(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 ग.ग. तथा सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 12 क.क. के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद द्वारा घोषणा करती है कि, जहाँ विनिर्माता, प्रथम चरण अथवा दूसरे चरण का डीलर, अथवा मर्चेन्ट निर्यातक सहित निर्यातक प्रथम दृष्टया निम्नलिखित में से किसी में जानबूझ कर शामिल पाया जाता है;

(क) डुयटी का भुगतान किये बिना तथा बीजक के बिना वस्तुओं को हटाना;

(ख) शुल्क भुगतान के लिए सही मूल्य घोषित किये बिना वस्तुओं को हटाना, जहाँ बिक्री मूल्य का एक भाग, बीजक मूल्य से अधिक, उसके द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसकी लेखा पुस्तिकाओं में उसका हिसाब नहीं है;

(ग) जिन दस्तावेजों के आधार पर उक्त क्रेडिट लिया गया है, उनमें विनिर्दिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के बिना सेनवेट क्रेडिट लेना;

(घ) बीजकों अथवा अन्य दस्तावेजों जिनके सम्बंध में व्यक्ति के पास इस विश्वास के कारण है, कि ये प्रमाणिक नहीं है, पर सेनवेट क्रेडिट लेना;

(ङ) उक्त बीजक में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के हस्तांतरण के बिना उत्पाद शुल्क बीजक जारी करना ;

(च) उत्पाद शुल्क अदा की गई बीजक अथवा अन्य दस्तावेजों जिनके सम्बंध में व्यक्ति के पास इस विश्वास के कारण है कि ये प्रमाणिक नहीं हैं, के आधार पर वापसी अथवा छूट का दावा करना, बोर्ड द्वारा अधिकृत एक अधिकारी सुविधाओं की वापसी के आदेश दे सकता है, अथवा इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट कुछ प्रतिबन्ध लगा है।

2. वापस ली जाने वाली सुविधाएँ तथा लगाए जाने वाले प्रतिबन्ध :

(1) जहाँ विनिर्माता पैरा 1 में विनिर्दिष्ट अपराधों को जानबूझ कर करने में प्रथम दृष्टया शामिल पाया जाता है, सुविधाओं पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं; अर्थात् :-

(i) निर्धारिती से शुल्क के मासिक भुगतान की सुविधा को वापस लिया जा सकता है, जिसके बाद उसे प्रत्येक खेप पर उत्पाद शुल्क का भुगतान वस्तुओं को हटाने के समय करना होगा ;

(ii) निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट के उपयोग करने से रोका जा सकता है, जिसके द्वारा उक्त क्रेडिट का उपयोग किये बिना उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने हेतु कहा जा सकता है:

बशर्त कि जहाँ व्यक्ति पारा 2 में यथा विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक प्रकार के अपराधों को जानबूझकर करने में दूसरी बार अथवा तदंतर शामिल पाया जाता है, उसकी फैक्टरी से वस्तुओं की प्रत्येक निकासी एक बीजक के अंतर्गत किए जाने के आदेश किए जा सकते हैं, जिसपर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक द्वारा उक्त वस्तुओं को फैक्टरी अथवा भाण्डागार से हटाने से पहले प्रतिहस्ताक्षर किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण 1:- यह स्पष्ट किया है, कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध पारा 4 के उपपारा (3) के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट लेने के लिये आदेश पारित कर सकता है, परंतु वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान के लिये क्रेडिट उपयोग में सन्तर्ध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2 - दुबारा अथवा अनुवर्ती अपराध के लिए, खंड (i) तथा (ii) में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्ध भी लगाए जा सकते हैं।

(2) जहाँ पहले चरण अथवा दूसरे चरण का डीलर पैरा 1 की धारा (घ) अथवा (च) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध को जानबूझकर करने में शामिल पाया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :- निलम्बन की अवधि के दौरान उक्त डीलर कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बीजक जारी नहीं करेगा। किंतु, वह अपना व्यापार जारी रख सकता है और बीजक में व्यापार जारी रख सकता है और बीजक में उत्पाद शुल्क प्रदर्शित किए बिना बिक्री बीजक जारी कर सकता है और ऐसी बीजक के अंतर्गत वस्तुओं के प्राप्तकर्ता को कोई सेनवेट क्रेडिट देय नहीं होगा।

(3) जहाँ कोई निर्यातक व्यापारी जानबूझकर पारा 1 के धारा (फ) में विनिर्दिष्ट प्रकार का अपराध करने का दोषी पाया जाता है, वहाँ स्वतः - सील करने की सुविधा वापस ली जा सकती है, जिसके बाद प्रत्येक निर्यात प्रेषण वहाँ के क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय उत्पाद अधिकारियों द्वारा जाँचा तथा सील किया जाएगा:

बशर्त कि किसी निर्माता, प्रथम या द्वितीय स्तर के डीलर या निर्यातक को बोर्ड द्वारा जारी किसी अन्य परिपत्र अथवा आदेश द्वारा अन्य सुविधा भी किसी विशिष्ट अवधि के लिए छीनी जा सकती है ;

4034 GI/06-2

3. आर्थिक सीमा :- इस अधिसूचना से संबंधित प्रावधान उन स्थितियों में ही लागू होंगे, जहाँ पारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराधों के संदर्भ में आरोपित शुल्क या सेनवेट क्रेडिट, 10 लाख रुपये से अधिक है।

4. प्रक्रिया:- (1) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद अथवा अपर महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद आसूचना, जैसा लागू हो, दस्तावेज तथा अन्य प्रमाणों के जाँच के बाद और अपने-आपको संतुष्ट करने के बाद कि उस व्यक्ति ने जान-बूझकर पारा 1 में वर्णित अपराध किया है, एक प्रस्ताव, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद आसूचना, जैसा लागू हो, को वापस ली जानेवाली सुविधाओं तथा लगाए जानेवाले प्रतिबंधों की सूची, उनकी समय-सीमाओं के साथ, जिस दौरान ये वापस लिये जाएँगे या प्रतिबंधित किए जायेंगे, जहाँ तक संभव हो, मामले में, पता चलने के तीस दिनों के भीतर, भेजेगा।

(2) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद आसूचना, जैसा लागू हो, प्राप्त प्रस्ताव की जाँच करेगा तथा प्रस्ताव के साथ प्राप्त दस्तावेज तथा प्रमाणों से अपने-आपको संतुष्ट करने के बाद यदि पाता है, कि ये प्रथम दृष्टया यह उचित विश्वास करने योग्य हैं, कि उस व्यक्ति ने जान-बूझकर पारा 1 में वर्णित अपराध किया है, उस प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं के साथ बोर्ड को भेज सकता है। तथापि मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद आसूचना, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की जा रही है, को अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर देगा और उसपर विचार करने के बाद ही वह अपनी अनुशंसा बोर्ड में भेजेगा।

(3) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद आसूचना से प्राप्त अनुशंसाओं की जाँच करेगा और वापस ली जानेवाली सुविधाओं और लगाए जानेवाले प्रतिबंधों संबंधी-उन समय सीमाओं के साथ जिसमें ये सुविधायें नहीं दी जायेंगी या जिस दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे- को विनिर्दिष्ट करते हुए एक आदेश पारित करेगा।

[फा. सं. 224/40/2006-के.उ.शु.-6]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2006

No. 32/2006-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 782(E).— In pursuance of rule 12CC of the Central Excise Rules, 2002, and rule 12AA of the CENVAT Credit Rules, 2004, the Central Government, hereby declares that where a manufacturer, first stage or second stage dealer, or an exporter including a merchant exporter is prima facie found to be knowingly involved in any of the following,-

- (a) removal of goods without the cover of an invoice and without payment of duty;
- (b) removal of goods without declaring the correct value for payment of duty, where a portion of sale price, in excess of invoice price, is received by him or on his behalf but not accounted for in the books of account;
- (c) taking of CENVAT Credit without the receipt of goods specified in the document based on which the said credit has been taken;
- (d) taking of CENVAT Credit on invoices or other documents which a person has reasons to believe as not genuine;

- (e) issue of excise duty invoice without delivery of goods specified in the said invoice;
- (f) claiming of refund or rebate based on the excise duty paid invoice or other documents which a person has reason to believe as not genuine,

an officer authorized by the Board may order for withdrawal of facilities or impose certain restrictions as specified in para 2 of this Notification.

2. Facilities to be withdrawn and imposition of restrictions:

(1) Where a manufacturer is prima facie found to be knowingly involved in committing the offences as specified in para 1, the following restrictions may be imposed on the facilities, namely:-

- (i) the facility of monthly payment of duties may be withdrawn and the assessee shall be required to pay excise duty for each consignment at the time of removal of goods;
- (ii) payment of duty by utilisation of CENVAT credit may be restricted and the assessee shall be required to pay excise duty without utilising the CENVAT credit:

Provided that where a person is found to be knowingly involved in committing any one or more type of offences as specified in para 1 for the second time or subsequently, every removal of goods from his factory may be ordered to be under an invoice which shall be countersigned by the Inspector of Central Excise or the Superintendent of Central Excise before the said goods are removed from the factory or warehouse.

*Explanation I.-* It is clarified that a person against whom the order under sub-para (3) of para 4 has been passed may continue to take CENVAT credit; however, he would not be able to utilize the credit for payment of duty during the period specified in the said order.

*Explanation II.-* For second time or subsequent offence, the restriction specified in clauses (i) and (ii) may also be imposed.

(2) Where a first stage or second stage dealer is found to be knowingly involved in committing the type of offence specified at clauses (d) or (e) of para 1, the registration granted under rule 9 of the Central Excise Rules 2002 may be suspended for a specified period.

*Explanation.-* During the period of suspension, the said dealer shall not issue any Central Excise Invoice. However, he may continue his business and issue sales invoices without showing excise duty in the invoice and no CENVAT credit shall be admissible to the recipient of goods under such invoice.

(3) Where a merchant exporter is found to be knowingly involved in committing the type of offence specified at clause (f) of para 1, the self sealing facility for export consignment may be withdrawn whereby each export consignment shall be examined and sealed by the jurisdictional Central Excise Officer:

Provided that any other facility available to a manufacturer, first stage or second stage dealer or an exporter provided by a circular or an order issued by the Board may also be ordered to be withdrawn for a specified period.

3. Monetary Limit.- The provisions of this notification shall be applicable only in a case where the duty or CENVAT Credit alleged to be involved in the offences specified in para 1 is more than Rs.10 lakhs.

4. Procedure.- (1) The Commissioner of Central Excise or Additional Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, after examination of records and other evidence, and after satisfying himself that the person has knowingly committed the offence as specified in para 1, may forward a proposal to the Chief Commissioner or Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, specifying the facilities to be withdrawn and restriction to be imposed and the period of such withdrawal or restrictions, within 30 days of the detection of the case, as far as possible.

(2) The Chief Commissioner of Central Excise or Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, shall examine the said proposal and after satisfying himself that the records and evidence relied upon in the said proposal are sufficient to form a reasonable belief that a person has knowingly committed the offences specified in para 1, may forward the proposal along with his recommendations to the Board. However, the Chief Commissioner of Central Excise or Director General of Central Excise Intelligence, before forwarding his recommendations, shall give an opportunity of being heard to the person against whom the proceedings have been initiated and shall take into account any representation made by such person before he forwards his recommendations to the Board.

(3) An officer authorized by the Board shall examine the recommendations received from the Chief Commissioner of Central Excise or Director General of Central Excise Intelligence and issue an order specifying the type of facilities to be withdrawn or type of restrictions imposed, along with the period for which said facilities will not be available or the period for which the restrictions shall be operative.

[F.No. 224/40/2006-CX-6]

RAHUL NANGARE, Under Secy.